साप्ताहिक

शहर सत्ता

RNI TITLE CODE - CHHHIN17596

सोमवार, 28 अप्रैल से 04 मई 2025

हम दिखाएंगे आईना...

वर्ष : 01 अंक : 08 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 03 में...

ढाई करोड़ की मशीन... डेढ़ करोड़ का खर्चा

पेज 12 में...

उरांव राजवंशीय का सुशासन

पेज 10 **चाल, चरित्र और चेहरे के साथ जुबान भी बदशक्ल...**

छालीवुड के 70 छलिया...

₹50 करोड़ के बजट वाली इंडस्ट्रीज में करोड़ों का कर अपवंचन

- 90 से 100 प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड, सिर्फ 70-80 ही बना रहे फ़िल्में
- छालीवुड की रंगीन दुनिया में टैक्स अनुपालन का काला सच उजागर
- टैक्स-श्रम नियमों की अनदेखी को लेकर कटघरे में प्रोडक्शन हाउस
- शूटिंग साईट में सुरक्षा की अनदेखी, क्रू मेंबर्स की जान जोखिम में
- महिला अधिकारों की अनदेखी, श्रम कानून का उल्लंघन

पुरन किरी
रायपुर

शहर सत्ता। वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इंडस्ट्री, विशेषकर एल्बमों के जरिये, तेजी से उभरी। उस दौर में कई प्रोडक्शन हाउसों ने बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया, जिससे आयकर विभाग की नजर उन पर पड़ी थी। लेकिन अब, जब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का आकार 20 से 30 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है, आयकर, GST और श्रम विभाग की अनदेखी की जा रही है। पहले जब सीडी का जमाना था तब एक गाना 15 से 20 हजार रूपये तैयार होता था अब यही एक गाना ऑडियो-वीडियो एल्बम के लिए 40 हजार से 3 लाख रूपये बजट को टच कर गया है।

अब सोशल मिडिया की वजह से यहाँ के गानों की लोकप्रियता भी बढ़ी है इसलिए बड़ी म्यूजिक कंपनिया जी म्यूजिक,सारे गा मा जैसी कंपनिया भी छत्तीसगढ़ में सम्भावना तलाश रही हैं। कारोबार फिल्म इंडस्ट्रीज का भी बढ़ा है। पहले सालभर में छोटी-बड़ी 4 से 5 फ़िल्में ही बनती थीं लेकिन आज छालीवुड का यह कारोबार भी 30 करोड़ के बजट आंकड़ों को छूने लगा है। इतने बड़े पैमाने पर लेन-देन के बावजूद, टैक्स अनुपालन को लेकर गंभीर लापरवाही देखी जा रही है।

फिल्म इंडस्ट्री में टैक्स का झोलझाल

छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय लगभग 90 से 100 प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड हैं। जिनमें से 70 से 80 छालीवुड के फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ही फिल्म निर्माण में सक्रीय है। इन प्रोडक्शन हाउसेज़ में से कुछ बड़े नाम जो साल में एक से दस फिल्मों तक का निर्माण कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर बड़े बजट की फ़िल्में बनाकर नाम तो कमाए परंतु प्रॉपर टैक्स अनुपालन नहीं कर रहे। इक्का-दुक्का प्रोडक्शन हॉउस को छोड़कर अगर आयकर, मनोरंजन कर, जीएसटी विभाग इनका संज्ञान ले तो बड़ा कर अपवंचन सामने आएगा।

छालीवुड के स्थापित प्रोडक्शन हॉउस

- सतीश जैन फिल्म्स (सतीश जैन)
- एन माही फिल्म्स (मोहित साहू)
- गोल्डन ड्रीम्स फिल्म्स (भारती वर्मा)
- गजेंद्र श्रीवास्तव फिल्म्स (गजेंद्र श्रीवास्तव)
- सुंदरनी फिल्म्स (वीडियो वर्ल्ड) (मोहन सुंदरनी)
- विजय सुंदरनी फिल्म्स (विजय सुंदरनी)
- लायरा फिल्म प्रोडक्शन
- मितान फिल्म्स
- राज वर्मा फिल्म्स (राज वर्मा)

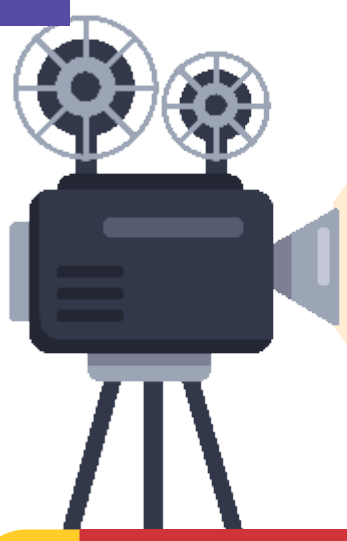

फिल्म निर्माण का औसत खर्च और समय

बजट	:	₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक
निर्माण समय	:	लगभग 6 महीने
शूटिंग अवधि	:	15 से 50 दिन

कलाकारों और टेक्नीशियनों की पारिश्रमिक दरें

हीरो-हीरोइन	:	₹50,000 से ₹25 लाख प्रति फिल्म
कैरेक्टर आर्टिस्ट	:	₹2,000 से ₹20,000 प्रतिदिन
कैमरा मैन	:	₹2,000 से ₹20,000 प्रतिदिन
डायरेक्टर	:	₹1 लाख से ₹20 लाख प्रति फिल्म

1 शूटिंग स्पॉट में श्रम कानून की ऐसे अनदेखी

- अनुबंध और वेतन में पारदर्शिता की कमी
- कलाकारों और टेक्नीशियनों से बिना अनुबंध के कार्य
- न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं होती

2 मनमानी कार्यावधि

- नियम विरुद्ध 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता है
- साप्ताहिक अवकाश और तय विश्राम समय का पालन नहीं

3 सेट पर सुरक्षा का अभाव

- शूटिंग के दौरान सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी।
- दुर्घटना के जोखिम के बावजूद कोई बीमा सुविधा नहीं।

4 महिला अधिकारों की अनदेखी

- लैंगिक समानता नियमों की अनदेखी
- यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं

5 बाल श्रम और प्रशिक्षु का शोषण

- बिना अनुमति के बच्चों से काम कराना।
- इंटर्न्स और असिस्टेंट्स से अत्यधिक कार्य लेना, बिना वेतन।
- शूटिंग के दौरान संभावित हादसों के लिए बीमा भी नहीं किया जा रहा

6 स्थानीय प्रतिभाओं के साथ भेदभाव

- बाहरी लोगों को तरजीह स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा
- बॉलीवुड की फ़िल्में, एल्बम रिकॉर्ड और वेब सीरीज राज्य में बन रही हैं
- बाहरी कलाकारों और स्थानीय अभिनेताओं के पारिश्रमिक में अंतर
- 90 % प्रोडक्शन हॉउस TDS नहीं काटते और जो काट रहे वो जमा नहीं कर रहे

इनकम टैक्स और GST के नियमों की अनदेखी

इनकम टैक्स एक्ट1961 के तहत TDS काटना अनिवार्य है। सेक्शन194/C के अंतर्गत कांट्रैक्ट आधारित भुगतान पर TDS सेक्शन 194(J)तहत प्रोफेशनल सेवाओं (जैसे एक्टर, डायरेक्टर) पर TDS लागु होता है। सेक्शन 194(H)कमीशन और ब्रोकरेज भुगतान पर TDS लगता है।
छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में श्रम विभाग के मानकों का भी गंभीर उल्लंघन शूटिंग स्पॉट पर हो रहा है।

उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई

टैक्सेशन की धरा 201(1A) के तहत कर अपवंचन पर ब्याज वसूलना। सेक्शन 271(C) के अंतर्गत TDS न काटने पर जितनी राशि काटनी थी, उतने का ही जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सेक्शन 276(B) TDS काटकर जमा न करने पर 3 महीने से 7 साल तक की कैद और जुर्माना। सेक्शन 234 (E)TDS रिटर्न देरी से भरने पर ₹200 प्रतिदिन का लेट फीस। GST के तहत (Goods and Services Tax Act, 2017) भी है।

- ₹20 लाख से अधिक टर्नओवर पर GST पंजीकरण अनिवार्य है
- फिल्म निर्माण व वितरण सेवाओं पर 18% तक GST लागू है
- GST अनुपालन नहीं करने पर दंड का है प्रावधान
- 10% टैक्स तक का जुर्माना (कम से कम ₹10,000)
- जानबूझकर अनदेखी करने पर 100% टैक्स या अधिक पेनल्टी
- सेक्शन 132 गंभीर मामलों में गिरफ्तारी और जेल का प्रावधान।

IT और GST के अलावा श्रम विभाग उदासीन

दशक पहले आयकर विभाग ने छालीवुड एल्बम निर्माताओं पर एक साथ धावा बोला था। उस वक्त सीडी का दौर था और कई म्यूजिक एल्बम औडियो-वीडियो बनाने वालों के कर अपवंचन की पड़ताल आयकर टीम ने किया था। उसके बाद से अब तक छालीवुड पर जीएसटी, श्रम विभाग और आयकर विभाग ने कार्रवाई तो दूर जांच पड़ताल तक नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में छालीवुड में फ़िल्में और गानों के एल्बम का काम और भुगतान नियमों की अनदेखी कर करोड़ों रूपये नकद में हो रहा है।

ढाई करोड़ की मशीन, हर साल डेढ़ करोड़ होगा खर्च

10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जलकुंभी हटाने के नाम पर खर्च

विशेष संवाददाता/विकास यादव

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर नगर निगम ने पिछले एक दशक में तालाबों पर 10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जलकुंभी हटाने के नाम पर खर्च कर दिए। सौंदर्यीकरण पर करीब 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जा चुके हैं।

पिछले साल बूढ़ातालाब में जलकुंभी हटाने और गाद निकालने के बड़ा काम किया गया था। इस पर ही करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी तरह शहर के सबसे बड़े तालाबों में शुमार महाराजबंध और राजातालाब से भी जलकुंभी हटाने के नाम पर रायपुर स्मार्ट सिटी और निगम लाखों रुपए खर्च कर चुका है।

तालाबों से जलकुंभी साफ करने वाली हार्वेस्टर मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। महापौर एजाज ढेबर ने बजट में इसका प्रावधान भी किया था, लेकिन यह मशीन नहीं खरीदी जा सकी। अलग-अलग क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर डेढ़ से ढाई करोड़ रुपए लागत वाली यह मशीन दो-तीन घंटे में करीब 20 एकड़ तालाब से जलकुंभी हटाने में सक्षम है। यानी हर साल करीब डेढ़ करोड़ का खर्च होगा। यह वर्तमान व्यवस्था से अधिक खर्चीला होगा। इसलिए प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई।

केमिकल ट्रीटमेंट खतरनाक

पं. रविशंकर विवि में एसोसिएट प्रोफेसर डा. शम्स परवेज का कहना है कि जलकुंभी हटाने के दो तरीके हैं। इनमें एक मैनुअल और दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट। मैनुअल तरीके में जब भी जलकुंभी उपजती है तो उसे मजदूरों की मदद से निकाल लिया जाता है। किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। दूसरा तरीका होता है केमिकल ट्रीटमेंट। यानी जलकुंभी निकालने का बाद तालाब में एक खास तरह का केमिकल डाला जाता है। इसका नुकसान यह होता है कि तालाब का पानी फिर निस्तार के लायक नहीं रह जाता। इससे जलीय जीव-जतुंओं के जीवन पर भी खतरा रहता है। तालाबों में आने वाले सीवेज वाटर, गंदगी इत्यादि के कारण जलकुंभी खुद ब खुद उपजते हैं।

राजातालाब सहित सभी तालाबों से जलकुंभी हटाना एक बड़ी समस्या है। हम जलकुंभी साफ करने वाली मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मशीन खरीदने के बाद जलकुंभी हटाना आसान हो जाएगा।

- मीनल चौबे, महापौर रायपुर

प्रमुख तालाबों पर खर्च

बूढ़ातालाब	-	2.75 करोड़
महाराजबंध	-	2.30 करोड़
डंगनिया तालाब	-	45 लाख
बंधवा तालाब	-	35 लाख
राजातालाब	-	55 लाख
नया तालाब	-	25 लाख
नरैया तालाब	-	25 लाख
नया तालाब	-	15 लाख
कटोरा तालाब	-	27 लाख
पहलदवा तालाब	-	17 लाख

सरकारी काम में अब नहीं होगी देरी छग में 13 सेवाओं का टाइमफिक्स

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के कार्यकलापों और सरकारी कामकाज को पुष्टता मिलेगी। अब तय टाइम में काम निपटाना अफसरों की जिम्मेदारी होगी। अगर लेट हुए, तो सीधे जवाबदेही तय होगी। सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकारी कामों के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में बड़े विभागों की 13 अहम सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है।

अब पर्यावरण मंजूरी हो, उद्योग से जुड़े लाइसेंस हों, माप-तौल सर्टिफिकेट बनवाना हो, टाउन प्लानिंग की मंजूरी लेनी हो या फिर जल संसाधन से जुड़ी कोई इजाजत लेनी हो सब कुछ तय टाइम में होगा। जो काम पहले महीनों लटकते थे, अब जल्दी निपटेंगे। सरकार यहीं नहीं रुकने वाली। प्लान है कि आने वाले टाइम में और भी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में लाया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ हर फील्ड में और तेज दौड़े। ये कदम राज्य में निवेश बढ़ाने से लेकर रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने तक हर लेवल पर फर्क डालेगा।

इन 13 सेवाएं जिनका अब टाइमफिक्स

- पर्यावरण मंजूरी (Environment Clearance)
- औद्योगिक लाइसेंस (Industrial License)
- माप-तौल प्रमाणन (Weights and Measures Certification)
- टाउन प्लानिंग अनुमोदन (Town Planning Approval)
- जल उपयोग परमिट (Water Usage Permits)
- भूजल उपयोग अनुमति (Ground Water Use Permit)
- फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण (Factory License Renewal)
- उद्योग स्थापना अनुमति (Industry Establishment Permission)
- वाणिज्यिक माप-तौल उपकरणों की सत्यापन (Commercial Weighing/Measuring Equipment Verification)
- निर्माण योजना स्वीकृति (Building Plan Approval)
- व्यावसायिक प्रतिष्ठान पंजीयन (Commercial Establishment Registration)
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Control Certificate)
- जल संरचनाओं की निर्माण अनुमति (Construction Permission for Water Structures)

आतंकी हमले में घायल पूजा का अम्बेडकर अस्पताल में उपचार

शहर सत्ता/रायपुर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी शहर निवासी श्री अरविंद अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती पूजा अग्रवाल घायल हो गई थीं। जान बचाने के प्रयास में उन्हें कंधे पर चोट लगी थी। आज जब उनका परिवार रायपुर पहुँचा, तो स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनका कुशलक्षेम पूछा और परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के निर्देश पर श्रीमती पूजा अग्रवाल का तत्काल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग में परीक्षण कराया गया। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रणय श्रीवास्तव ने उनकी विस्तृत जांच की। डॉ. प्रणय ने बताया कि श्रीमती पूजा अग्रवाल के दाहिने कंधे में हल्का फ्रैक्चर पाया गया है। अम्बेडकर अस्पताल पहुँचते ही उनके दाहिने कंधे और रीढ़ का एक्स-रे किया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोलीबारी के दौरान जान बचाने के लिए जमीन पर लेटने के कारण उन्हें चोट लगी होगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने जानकारी दी कि मरीज को सभी आवश्यक दवाइयाँ दी गई हैं और उन्हें फॉलोअप हेतु परामर्श दिया गया है। आतंकी हमले के भयावह अनुभव के चलते पूरा परिवार मानसिक रूप से भी व्यथित था, इसलिए चिकित्सकों द्वारा उनकी काउंसलिंग भी की गई और उन्हें ढाढ़स बंधाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने पूजा अग्रवाल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से खड़ी है। उन्होंने डॉक्टरों को उपचार में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। पूजा अग्रवाल एवं उनके परिवार को यदि आगे भी किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार हर संभव मदद प्रदान करेगी।

गर्मी बढ़ने के साथ 7000 मेगावॉट पहुंची बिजली की डिमांड

पीक लोड ऑवर में 800 मेगावाट बिजली सेंट्रल पुल से पड़ रही खरीदनी

टीकम वर्मा/ प्रमुख संवाददाता
मो. 7725073133

शहर सत्ता/रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म है। बीते वर्ष मई की तुलना में मौजूदा दौर में 638 मेगावाट बिजली की खपत ज्यादा है। बीते वर्ष मई महीने में बिजली की खपत 6,368 मेगावॉट के करीब थी। वर्तमान में यह बढ़कर 7,006 मेगावाट हो गया है। लिहाजा एक साल में तकरीबन 10 प्रतिशत मांग बढ़ गई है। पीक लाेड अवर में मांग और ज्यादा बढ़ जा रही है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय पुल से महंगे दाम पर 800 मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ रही है।

सालभर में बढ़ाई गई सब स्टेशनों की संख्या

बीते एक साल में 33/11 केवी के 56 नए उपकेंद्र बनाए गए हैं। 30 उपकेंद्रों में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये गए हैं तथा 50 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है। घरेलू बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 11/0.4 केवी क्षमता के 15 हजार 198 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। प्रदेश में 33 केवी, 11 केवी तथा निम्नदाब लाइनों की कुल लंबाई 3,98,559 सर्किट किमी है।

ऐसे कर रहे बिजली आपूर्ति

प्रदेश में पैदा होने वाली बिजली को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अति उच्चदाब टॉवर लाइनों तथा उपकेंद्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा की जाती है। जिसके कारण उच्चदाब उपकेंद्रों की कुल संख्या 132 से बढ़कर 135, उच्चदाब ट्रांसफॉर्मरों की संख्या 335 से बढ़कर 362 हो गई है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में ट्रांसफॉर्मरों की कुल क्षमता 24,227 एमवीए थी वह बढ़कर 26,475 एमवीए हो गई है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई जो दिसंबर 2023 में 13,934 थी वह बढ़कर 14,462 सर्किट किलोमीटर हो गई है।

अप्रैल महीने के शुरुआत से ही भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर बिजली कंपनी को झेलनी पड़ रही है। डिमांड और जनरेशन के बीच भारी अंतर आना शुरू हो गया है। बीते वर्ष मई के महीने में अधिकतम डिमांड 6,368 मेगावॉट पहुंची थी। इस साल एक महीने पहलेअप्रैल में ही 10 प्रतिशत बढ़कर 7,006 मेगावाट तक डिमांड पहुंच गई। पीक लोड अवर में यह आंकड़ा और भी बढ़ जा रहा है। डिमांड और जनरेशन के बीच बढ़ते अंतर का असर फ्यूजकाल सेंटर में बैठे कर्मचारियों पर भी हो रहा है। सेंट्रल काल सेंटर में प्रदेश के 65 लाख उपभोक्ताओं में से 1 लाख 56 हजार बिजली गुल होने को लेकर शिकायतें दर्ज कराई है। भीषण गर्मी के दौर में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी ने किसानों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों के अलावा आम उपभोक्ताओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए पॉवर एक्सचेंज और बैंकिंग के साथ ही एचपीडीएएम (High Prices Day Ahed Market) के जरिये मंहगी दरों पर बिजली खरीदकर आपूर्ति की जा रही है।

पावर प्लांटों से एक्सचेंज आफर में बिजली

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्षमता 2978.7 मेगावॉट है। राज्य सरकार से अनुबंध के आधार पर सेंट्रल पुल से 3,380 मेगावॉट बिजली मिलती है। राज्य में स्थापित सोलर संयंत्र से लगभग 700 मेगावॉट बिजली मिलती है। प्रदेश में दिन के समय मांग की तुलना में अधिक बिजली रहने पर छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों को बिजली देता है। दिन के समय बिजली की अधिकता रहने पर अभी हिमाचल प्रदेश को 250 मेगावॉट बैंकिंग के जरिये बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह बिजली हिमाचल प्रदेश जुलाई, अगस्त, सितंबर में लौटाएगा। इसी तरह पंजाब और दिल्ली को पहले 50-50 मेगावॉट बिजली दी गई थी, जिसे अभी रात के समय दोनों राज्य लौटा रहे हैं।

दिन में कम और रात में बढ़ जाती है डिमांड

छत्तीसगढ़ में बिजली की औसत मांग दिन में 5,120 मेगावॉट रहती है। पीक लोड ऑवर (शाम 6 बजे से रात तक) में यह मांग 6,500 से 7,000 मेगावॉट से अधिक पहुंच जा रही है। डिमांड और जनरेशन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए तकरीबन 800 मेगावॉट बिजली HDPM के जरिये ली जा रही है। 14.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है। जब देश के अन्य राज्यों की मांग खुलती है तब प्रति यूनिट बिजली की दर भी बढ़ जाती है।

डिमांड पूरी करने ऐसे कर रहे मैनेज

प्रतिदिन एक अलग टीम प्रदेश में संभावित डिमांड और जनरेशन के बीच तालमेल बैठाते हुए पॉवर परचेज करती है। सामान्य तौर पर राज्य में उत्पादित बिजली की दर 4 से 8 रूपए प्रति यूनिट तक रहती है। पीक लोड अवर में बिजली कंपनी चार गुना अधिक दाम पर बिजली खरीद रही है।

छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी, छोड़ना होगा भारत

शहर सत्ता/भिलाई/रायपुर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार ने जहां एक ओर तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है तो दूसरी ओर अल्पकालिक वैध वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। ऐसे में अब देशभर में पाकिस्तानी नागरिकों की ताबड़तोड़ तलाश की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में आकर रह रहे पाकिस्तानियों की तो यहां करीब 2000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक रहे हैं। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि अकेले रायपुर में 1876 पाकिस्तानी रह रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। हालांकि ये भी सिंध प्रांत इलाके से आए हुए हैं। अब इन पाकिस्तानियों को गृह मंत्रालय के फैसले का इंतजार है। देखने वाली बात होगी कि क्या इन पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी आज सुबह से पाकिस्तानी नागरिकों की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस की टीम शहर के अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर संदिग्धों की पहचान कर रही है। सर्चिंग के दौरान पुलिस की टीम ने भिलाई के बॉम्बे आवास से 10, हथखोज से 8 और सुपेला कर्बला मैदान से 6 संदिग्धों की पहचान की है। फिलहाल पुलिस सभी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। केंद्र के फैसले के मुताबिक भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा अल्पकालिक वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे।

एसएसपी सिंह और आईजी मिश्रा के बेहतरीन समन्वय से घटने लगा राजधानी का क्राइम ग्राफ

शहर सत्ता/रायपुर। आमतौर पर रायपुर पुलिस में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों में बहुत काम ही पटरी बैठते देखा गया है। तत्कालीन एसएसपी और आईजी के मध्य सम्प्रभुता को लेकर पूर्व में कई विवाद सुर्खियां भी बनीं। सेवानिवृत DGP दुर्गेश माधव अवस्थी, DGP (Rtd)अशोक जुनेजा और DGP जीपी सिंह और ADG दीपांशु काबरा जैसे कई खाटी IPS राजधानी रायपुर की कमांड सम्हाल चुके हैं। अतिश्योक्ति भी नहीं होगी की इन जैसे तेजतर्रार अधिकारीयों के बीच ईगो भी दीखता था। लेकिन रायपुर पुलिस के लिए ऐसे कम ही मौके देखने को मिले जब पुलिस कप्तान और आईजी रेंज में पटरी बैठी हो। खुशकिस्मती ही कहेंगे कि उम्र में 19-20 का ही फर्क होने के बावजूद SSP डॉ लाल उमेद सिंह और IG अमरेश मिश्रा के बीच महक़माई प्रतिस्पर्धा नहीं बलकि बेहतरीन समन्वय है। इसलिए राजधानी रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना, चोरी, नशे के कारोबार पर काफी कंट्रोल हुआ है। आईजी अमरेश मिश्रा की प्लानिंग, रेंज अधिकारी की योजनाओं पर अनुभव के मुताबिक पालन करने से एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह की कप्तानी में राजधानी की पुलिसिंग अब मुस्तैद दिखने लगी है।

पांच महीने पहले राजधानी रायपुर में क्राइम ग्राफ हाई था। यहाँ 20 गैंग एक्टिव थे। मर्डर, ड्रग्स तस्करी और कई अवैध धंधे; नाबालिग भी पुलिस के लिए सिरदर्द थे। चाकूबाजी आम थी। लेकिन SSP लाल उमेद के आने और IG अमरेश मिश्रा के निदेशन पर इन जरायम पेशों पर नकेल कसने में राजधानी पुलिस काफी हद तक नियंत्रण हासिल कर ली है।

दोनों अफसर रायपुर से बेहतर वाकिफ़

एसएसपी SSP डॉ लाल उमेद सिंह राजधानी रायपुर में बतौर CSP, ASP पदस्थ रहे हैं। रायपुर के अपराधों और अपराधियों की उन्हें बेहतर समझ भी है। इसी तरह IG अमरेश मिश्रा पूर्व में रायपुर की पुलिस कप्तानी कर चुके हैं। महकमें में उनके गुस्से और जीरो टॉलरेंस से सभी वाकिफ हैं। राजधानी रायपुर को भी वो जानते हैं। दोनों ही अधिकारीयों की इसी काबिलियत और बिना किसी की सीमा का अतिक्रमण किये रायपुर में क्राइम प्रिवेंशन में जुटे हैं।

अपराधों का गिरा ग्राफ

- बाहरी राज्यों से अवैध हथियारों की आवक
- गली के गुंडों और चाकूबाजी पर कंट्रोल
- क्रिकेट सट्टे हेतु म्यूल बैंक एकाउंट वालों की मुश्केंं कसीं
- निगरानीशुदा और आदतन अपराधियों पर निगरानी
- अड्डेबाजी और बदमाशों की लगने वाली जमघट बंद
- नाबालिगों की सक्रियता की रोकथाम के लिए काउंसलिंग
- नशे के कारोबारी, नशेड़ियों के खिलाफ समय समय पर अभियान

इन गिरोहों पर सख्ती से रोकथाम

1, राजा गैंग, 2, करीम लाला गैंग, 3, CG DON गैंग, 4, चीरा गुड्डू गैंग, 5, गवली गैंग, 6, दिनेश M गैंग, 7, AK गैंग, 8. ST गैंग, 9. ईरानी गैंग, 10. कंवर गैंग के अलावा कई गली के गुंडों की फेहरिस्त तैयार की गई है। रायपुर पुलिस की सख्ती और एसएसपी की हिदायतों के बाद थाना प्रभारी भी कोताही नहीं बरत रहे।

डोंगरगढ़ रोप-वे हादसा...मां बम्लेश्वरी समिति पर FIR

फ्लक्चुएशन के आरोप पर कंपनी और बिजली विभाग में तकरार, शिकायत दर्ज

शहर सत्ता/डोंगरगढ़/रायपुर। डोंगरगढ़ में हुए रोप-वे हादसे के बाद अब मां बम्लेश्वरी रोप-वे संचालन समिति पर एफआईआर दर्ज की गई है। समिति पर डोंगरगढ़ थाने में FIR भाजपा की ओर से की गई है। वहीं, रोप-वे संचालक कंपनी के मुताबिक फ्लक्चुएशन के कारण हादसा हुआ। इस पर बिजली विभाग और कंपनी भी आमने सामने हो गई है। बिजली विभाग ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कंपनी के खिलाफ अलग से शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जिला कलेक्टर ने रोप-वे हादसे की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। जो 7 दिन में जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेगी।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

गम, इलाज और सवालात...

यह स्पष्ट है कि कश्मीर की नई कहानी की पटकथा ने देश की सीमा पार की दुष्ट शक्तियों और उनके समर्थकों में चिंता पैदा कर दी है। इसलिए, यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि घाटी में 25 साल से भी ज़्यादा समय में सबसे ख़तरनाक हमला, पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा कश्मीर पर हाल के दिनों में की गई सबसे ख़तरनाक हरकतों में से एक के ठीक बाद हुआ। पिछले हफ़्ते ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए, सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कश्मीर को इस्लामाबाद की "गले की नस" बताया और दो-राष्ट्र सिद्धांत का हवाला दिया।

आतंकवादियों का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में चल रहे आर्थिक पुनरुद्धार को पटरी से उतारना और केंद्र शासित प्रदेश में समय को पीछे धकेलना था। घाटी में पुनरुत्थान के केंद्र में पर्यटन रहा है। यह याद रखने की जरूरत है कि आगे का रास्ता कश्मीर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। मंगलवार को अपने प्रियजनों को खोने वालों की भरपाई कोई नहीं कर सकता।

देश के कर्ता धर्ताओं को हमलों के लिए खुद की और दुश्मन देश की जवाबदेही तत्काल तय की जानी चाहिए। मंगलवार के हमले के अपराधियों की तलाश और सुरक्षा में खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाने के साथ ही सरकार को चिंताजनक बदलाव के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए — तीर्थयात्री, प्रवासी और अब, पर्यटक भी आतंकी हमले के निशाने पर आ गए हैं। आतंकवादियों ने स्पष्ट रूप से अधिकतम प्रचार पाने के लिए अपने हमलों का समय भी तय किया है।

उदाहरण के लिए, पिछले साल जून में, उन्होंने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर उस दिन घात लगाकर हमला किया, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिपरिषद शपथ ले रहे थे। अक्टूबर में, आतंकवादियों ने उमर अब्दुल्ला सरकार के सत्ता में आने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद छह प्रवासी श्रमिकों और एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब, पहलगाम हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा के साथ हुआ है, जो इस्लामी दुनिया के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक है।

इस पर भी हमें विचार करना होगा कि इस दुस्साहस की आखिर क्या वजह होगी। क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही तरह से अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है। अगले दिन, जब दिल्ली कोई प्रतिक्रिया तैयार करेगी, तो उसे इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भारत के पक्ष में है - और राष्ट्र दुख और दर्द दोनों में एकजुट है। लेकिन सभी के दिल में कई तरह के सवालात भी कौंध रहे हैं आखिरकार...कब, कौन, क्यों और कैसे ? फ़िलहाल सभी बयानबाजी से बचें जो भड़काऊ लग सकती है - क्योंकि विभाजनकारी होने का कोई भी प्रयास केवल आतंकवादियों के हाथों में खेलना होगा।

पहलगाम म होय आतंकी हमला के बाद केंद्र सरकार ह हमर देश म राहत जम्मो पाकिस्तानी मनला तुरते भारत ल छोड़ के जाए के आदेश जारी करे हे जी भैरा तब इहाँ आगू च ले राहत पाकिस्तानी नागरिक मनला काबर नइ खेदारे जावत हे तेने ह मोला थोकिन अनफभिक जनावत हे.

हमरो इहाँ पहिलीच ले पाकिस्तानी नागरिक मन हें जी कोंदा?

वाह.. रायपुरे जिला म 18 सौ पाक नागरिक हें.. एमा के कतकों झन हमर देश के नागरिकता माँगत हें, फेर अभी उनला मिल नइ पाए हे.

वाह भई.. हमला तो एकर गमे नइ रिहिसे?

गजब दिन होगे संगी ए मनला इहाँ आके राहत, फेर अभी तक ए मन इहाँ के भाखा संस्कृति ल आत्मसात नइ करे हें.. मोला लागथे के जे मन संबंधित क्षेत्र के भाखा संस्कृति ल आत्मसात नइ करयँ उनला वो क्षेत्र म रहे बसे के अनुमति नइ देना चाही.. हमर छत्तीसगढ़ ल तो धरमशाला बना डारे हें.. बंगलादेशी अउ तिब्बती मनला इहें लान के खुसेरिन अउ अब पाकिस्तानी मन बर घलो अइसने करे जावत हे.. कूड़ादान बना डारे हें ए पबरित भुइया ल.. कहूँ के कचरा होवय इहें लान के कूढ़ो देथें.

केंद्र सरकार ल संबंधित क्षेत्र के लोगन के उँकर भावना के घलो चेत राखना चाही तब कोनो किसम के अनुमति देना चाही।

पाकिस्तान की शामत, अब ना बाढ़ की खबर, ना सूखे की चेतावनी...

हिमांशु शुक्ला

सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाकिस्तान की शामत आना तय है। भारत ने पाकिस्तान को एक आधिकारिक पत्र के जरिए सूचित किया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. पत्र में भारत ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा निरंतर हो रहे सीमा-पार आतंकवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी इस फैसले को लेकर कई सवालात हैं। कुछ के जेहन में यह है कि तीन नदियों का रुख भारत बदल देगा।

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा गया है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है और 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है. भारत की मार से पाकिस्तान अंदर तक हिल गया है और नेता गीदड़भभकी देने लगे हैं. सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान पर संकट के बादल हैं. बाढ़ या सूखा... दोनों से पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है. हालात कुछ ऐसे हैं कि PAK को खुद पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है?

क्या है सिंधु जल संधि?

साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था. संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था. जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर अधिकार दिया गया था, जो जम्मू-कश्मीर से होकर बहती हैं. सवाल उठ रहा है कि जल-बंटवारे के समझौते के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?

अब क्या बदलेगा?

1. इंडस जल आयुक्तों की बैठकें बंद

अब दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होंगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे. दरअसल, संधि के तहत दोनों देशों के दो आयुक्तों को साल में एक बार बारी-बारी से मिलने की व्यवस्था दी गई थी. भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के बाद अब ऐसी कोई बैठक नहीं होगी.

2. जल संबंधी आंकड़े नहीं मिलेंगे

भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा. इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना बढ़ सकती है। संधि के तहत भारत, पाकिस्तान को समय पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता आ रहा था. इसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी. नदी के प्रवाह को साझा करना और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट दिया जाता था. अब पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर के बारे में जानकारी की कमी के कारण संभावित सूखे या बाढ़ का खतरा है।

3. परियोजनाओं के बारे में नहीं मिलेगी जानकारी

भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपने जलविद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह-मशविरा किए आगे बढ़ा सकेगा. यानी दोनों देशों के बीच सूचना का प्रवाह रुक जाएगा. इस संधि ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को चिह्नित करने का अधिकार दिया था।

4. पाकिस्तानी आयुक्त को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश नहीं

पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, जिससे उन्हें भारतीय परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी. इससे पहले पाकिस्तान के आयुक्त पश्चिमी नदियों और भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति या रिपोर्ट लेने के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा करते आ रहे थे।

5. वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं

अब स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी. सिंधु जल संधि के अनुसार, स्थायी सिंधु आयोग (PIC), सिंधु प्रणाली के बंटवारे का प्रबंधन करने के लिए द्विपक्षीय निकाय है. इसे नदियों के साझा उपयोग पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है. लेकिन भारत द्वारा समझौते को सस्पेंड किए जाने के कारण वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि प्रणालियों के लिए जोखिम पैदा होगा।

आइये करें शून्य की खोज

हिमांशु शुक्ला

शून्य की खोज के विषय में किसी ने ब्रह्मभट्ट का नाम लिया तो किसी ने आर्यभट्ट का नाम लिया। इनके अलावे भी बहुत से दावे किए गए लेकिन सहमति न बन पाई।

'संख्यास्थाननिरूपणम्' में आर्यभट्ट ने लिखा:

एकं च दश च शतं च सहस्रं तु अयुतनियुते तथा प्रयुतम्।

कोट्यर्बुदं च वृन्दं स्थानात्स्थानं दशगुणं स्यात् ॥

मान लाया गया कि शून्य का अविष्कार ५ वीं सदी में आर्यभट्ट ने किया। हम भारतीय भी इतने पर ही खुश हो लेते हैं कि कम से कम विश्व इसे भारत की उपलब्धि तो मानता है।लेकिन दबी जुबान में लोगों ने यह भी कहा कि अगर ५वीं सदी में शून्य का अविष्कार हुआ तो हजारों वर्ष पूर्व रावण के दस सिर कैसे हुए?

बड़े वर्ग ने यही सोच कर कि विश्व ने तो मान लिया है, इसको छोड़ दिया। लेकिन यह तो एक कड़ी थी, अगर विश्व इसे और प्राचीन मानता तो मुख्य बात कि सनातन धर्म कितना प्राचीन है यह बात भी विश्व के सामने आने लगती।

यजुर्वेद १७/२ की ऋचा कहती है:

इमा मे अग्नऽ इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदम् समुद्रश् च मध्यं चान्तश् च परार्धश् चैता मे अग्नऽ इष्टका धेनवः सन्त्व् अमुत्रामुष्मिंल् लोके।।

अब यहाँ बड़ा प्रश्न उठता है कि यजुर्वेद की ऋचा प्राचीन है कि 'आर्यभट्ट'?

आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? जब विश्व ने यह मान लिया है कि शून्य भारत कि खोज है। लेकिन साहब! एक 'शून्य' की आपने क्या कीमत चुकाई? यह सोचिये। पहले तो वो कहते हैं कि- The Vedas are a collection of hymns and other ancient religious texts written in India between about 1500 and 1000 BCE. – Ancient History Encyclopedia लेकिन जाहिर तौर पर अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया क्योंकि तब तो इसका श्रेय भी ईश्वर को देना पड़ता जिन्होंने श्रुतियों के माध्यम से 'ब्रह्मा' को वेदों का बोध कराया या कम से कम यजुर्वेद अध्याय १७ के ऋषि 'विश्वकर्मा भौवन' को तो देना पड़ता है। जिन्होंने यह ऋचा 'निचृत आर्षी त्रिष्टुप' छंद में संकलित की। इसके बाद प्रश्न उठाया गया कि यह शून्य '०' ऐसा नहीं है। अरे, अब तो बात ही समाप्त हो गई। लोग भी इस विषय पर शांत हो गये। लेकिन क्या इतने से सब समाप्त हो गया कि अथर्ववेद में शून्य नहीं है?

वास्तव में वेदों में ईश्वर, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति-रिवाज समेत सभी विषयों से संबंधित ज्ञान है। वेदों की ऋचाएं तो गणित के नियमों से ही बंधीं हैं।

अब शून्य कैसे है? तो इसका उत्तर हैं – 'कटपयादी प्रणाली'

कटपयादी, यह प्राचीन काल से संख्या को कूटबध्द करने की पध्दति है। संस्कृत वर्णमाला में जो अक्षर हैं, उन्हे १ से ० संख्या के साथ जोड़ने से कटपयादी संख्या तैयार होती है। यह लंबे अंक सूत्र ज्ञात करने तथा छंद के द्वारा निष्कर्ष निकालने की योग्यता प्रदान करती है। कटपयादि प्रणाली के माध्यम से ही पाई (π) का मान दशमव से १७ स्थान तक सटीकता से निकाला गया। सनातन धर्म का विज्ञान इतना विकसित रहा है कि आज तक भी आधुनिक विज्ञान केवल उनके किसी सूत्र को सुलझा ले, इतने तक का ही खोज कर पाया है। यह भी तय है कि विश्व के सभी धर्म, धर्म – गुरु और विज्ञान अगर विकास के मार्ग पर बढ़ेंगे तो वह मार्ग सनातन धर्म का मार्ग ही होगा, भले ही वह इसे माने या न माने।

न्याय जरूर होगा : पीएम मोदी

मन की बात में पहलगाम हमले के पीड़ितों से प्रधानमंत्री ने किया वादा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए इस हमले से मन में गहरी पीड़ा है। हमारे देश के लोगों में जो आक्रोश है, वो पूरी दुनिया में भी है। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कड़ी निंदा की। विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

पहलगाम हमले का किया जिक्र

पीएम ने कहा, 'पहलगाम में हुआ ये हमला, आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल-कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। देश के दुश्मनों को, जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया।'

उन्होंने कहा कि आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं, कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता, आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है।

पीड़ितों से किया न्याय का वादा

पीएम ने कहा हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा।

अब तक 7 आतंकियों के ठिकाने जमींदोज

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई के दौरान एक और संदिग्ध आतंकवादी के घर पर बम विस्फोट किया गया. यह कार्रवाई पहलगाम में हुए हमले के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. इस बार उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में फारूक अहमद तड़वा के घर को निशाना बनाया गया. फारूक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा हुआ है. अधिकारियों ने उसके घर को बम से उड़ाया. हाल के दिनों में आतंकवादियों के कई घर इस तरह ध्वस्त किए जा चुके हैं. पिछले 48 घंटों में छह आतंकवादियों या उनके साथियों के घर गिरा दिए गए हैं.

पाक वापसी के लिए अटारी बॉर्डर पर लगी कतारें

चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। सार्क वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर निकलने की समयसीमा 26 अप्रैल को समाप्त हो गई, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वालों को छोड़कर बाकी के लिए यह आज यानी रविवार, 27 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध हैं। किशोरी सरिता ने रोते हुए कहा, 'मेरी मां भारतीय हैं और उन्हें हमारे साथ पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है,' उसे नहीं पता कि वह उनसे कब मिल पाएगी। वह, उसका भाई और पिता रविवार को अटारी सीमा पर भारत से बाहर निकलने के लिए कतार में खड़े सैकड़ों लोगों में शामिल थे।

पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांटना है : स्वामी विज्ञानानंद

नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है. इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं इसी बीच हिंदू मेनिफेस्टो किताब के लेखक स्वामी विज्ञानानंद ने पाकिस्तान पर निशाना है. उन्होंने कहा, "शत्रु के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से उसे नष्ट कर देना चाहिए. उन्होंने कहा है कि वो PM मोदी का समर्थन करते हैं.

'नहीं दोहरानी चाहिए पुरानी गलतियां'

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है और नागरिक के तौर पर हम उसका समर्थन करते हैं. हिंदू मेनिफेस्टो भी यही कहता है कि शत्रु को हराना और उसे नष्ट करना चाहिए. शत्रु को हराने के बाद उसे पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी है ताकि वह फिर से उठकर वापस न आ सके. उन्होंने कहा कि पहले हमने 1948, 1965, 1971 और 1999 में गलतियां कीं और अब हमें इन्हें दोहराना नहीं चाहिए. छोटी-छोटी घटनाओं से हमारी सुरक्षा तय नहीं हो सकती. हमें अंतिम और निर्णायक कदम उठाना होगा.

'नहीं चलेगा अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम'

उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जनरल ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को पांच हिस्सों में बांट देना चाहिए. सिंध, बलूचिस्तान, पीओके, पठानिस्तान और पंजाब को अलग कर देना चाहिए. इससे पाकिस्तान 50 साल तक शांत रहेगा.

उन्होंने कहा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. अगर पाकिस्तान से निपटना है तो एक फाइनल समाधान होना चाहिए. हिंदू मेनिफेस्टो के हिसाब से, शत्रु को हराना और उसे नष्ट करना हमारा धर्म है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो शत्रु फिर से खड़ा हो सकता है.

पानी के बाद अब दवाओं के लिए तरसेगा पाकिस्तान

इमरजेंसी के हालात से बचने की तैयारी में जुटा फार्मा सेक्टर

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान पर कई मायनों में संकट मंडराता दिख रहा है. ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दवाओं की भी किल्लत हो सकती है. जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पाकिस्तान दवाओं को लेकर कच्चे माल के 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक भारत पर निर्भर है, जिसमें सक्रिय दवा सामग्री (API) और कई उन्नत चिकित्सीय उत्पाद शामिल हैं. पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी (DRAP) ने पुष्टि की है कि हालांकि दवा क्षेत्र पर प्रतिबंध के प्रभाव के बारे में कोई औपचारिक अधिसूचना नहीं दी गई है, लेकिन आकस्मिक योजनाएं पहले से तैयार हैं.

चीन, रूस और यूरोप में तलाश रहा विकल्प

DRAP के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2019 के संकट के बाद हमने ऐसी इमरजेंसी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी. अब हम अपनी दवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रहे हैं. DRAP अब चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों से वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है. एजेंसी का लक्ष्य एंटी-रेबीज वैक्सीन, एंटी-स्नेक वेनम, कैंसर थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और अन्य महत्वपूर्ण जैविक उत्पादों सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

तस्करी के जरिए पाकिस्तान में आती हैं दवाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय को अभी तक दवा आयात की स्थिति को स्पष्ट करने वाला कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है, जबकि सरकार ने भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की है. दवा क्षेत्र को डर है कि सप्लाई चेन में रुकावट से पाकिस्तान में गंभीर समस्या हो सकती है. पाकिस्तान में दवाओं के काला बाजार को लेकर भी स्थिति गंभीर है, जहां अपंजीकृत और अस्वीकृत दवाएं पूर्वी सीमा के माध्यम से पाकिस्तान में तस्करी के जरिए आती हैं.

धमकी देते-देते पीछे हट गया पाकिस्तान

इस्लामाबाद। शुक्रवार को जहां पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी भारत को हमले की धमकी दे रहे थे वहीं शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैकफुट पर दिखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की किसी भी "निष्पक्ष और पारदर्शी" जांच में शामिल होने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है. 22 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में अंधाधुंध फायरिंग की थी. पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में पासिंग-आउट परेड को संबोधित करते हुए, शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बिना किसी सबूत के आधारहीन और झूठे आरोप लगा रहा है।

आखिर आजकल क्यों आते हैं इतने भूकंप?

इस अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

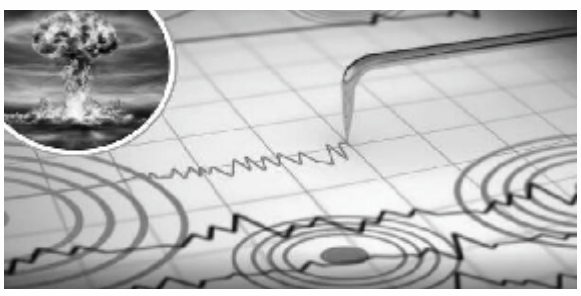

वाशिंगटन। वाशिंगटन से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में नई चिंता खड़ी कर दी है. लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च स्टडी में दावा किया है कि कुछ भूकंप वास्तव में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट भी हो सकते हैं. यह रिसर्च जोशुआ कारमाइकल के नेतृत्व में की गई. इसे अमेरिका के सीस्मोलॉजिकल सोसायटी के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है.स्टडी के अनुसार, भूकंप से लगने वाले झटकों और सीक्रेट न्यूक्लियर ब्लास्ट के झटकों के बीच अंतर करना मुश्किल है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही तकनीक ने काफी प्रगति कर ली है, फिर भी जब भूकंप और परमाणु विस्फोट एक साथ होते हैं या उनके संकेत मिल जाते हैं तो सबसे आधुनिक डिजिटल डिटेक्शन तकनीक भी सही पहचान नहीं कर पाती.

उत्तर कोरिया का उदाहरण लिया गया

रिसर्च में उत्तर कोरिया का उदाहरण प्रमुख रूप से दिया गया है. पिछले 20 साल में उत्तर कोरिया ने छह परमाणु परीक्षण किए हैं. परीक्षण स्थलों के आसपास भूकंप निगरानी उपकरणों की संख्या बढ़ने के बाद यह देखा गया कि इन क्षेत्रों में लगातार छोटे-छोटे भूकंप आते रहे हैं. इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु परीक्षण और भूकंप के संकेत एक-दूसरे में इतने अधिक घुल सकते हैं कि अंतर कर पाना कठिन हो जाता है. जोशुआ कारमाइकल और उनकी टीम ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पी-तरंगों और एस-तरंगों के रेसियो का विश्लेषण किया. उन्होंने एक तकनीक विकसित की, जो 1.7 टन के गुप्त दबे हुए विस्फोट का 97 प्रतिशत सटीक पता लगा सकती है. लेकिन जब भूकंप के झटके और विस्फोट की शॉकवेव 100 सेकंड के भीतर और 250 किलोमीटर के दायरे में आती है तो इसी तकनीक की सटीकता घटकर मात्र 37 प्रतिशत रह जाती है.

यूक्रेन के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार रूस

नई दिल्ली। सालों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं. क्रेमलिन ने शनिवार (26 अप्रैल, 2025) को कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के शांति वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है. इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की थी.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, "ट्रंप के दूत विटकॉफ के साथ कल की बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया कि रूस बिना किसी पूर्व शर्त के यूक्रेन के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है." उन्होंने कहा कि पुतिन ने अतीत में भी कई बार यह बात दोहराई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को कहा था कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता 'करीब' है.

मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को 54 रन से दी शिकस्त

लखनऊ। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को 54 रनों से हराया। लखनऊ ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, लेकिन सूर्यकुमार यादव और रियान रिक्लेटन की अर्धशतकीय पारी की मदद से मुंबई ने 20 ओवर में सात विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 161 रन पर ऑलआउट हो गई। मुंबई के लिए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवर में 22 रन देकर चार विकेट झटके। बुमराह इसके साथ ही मुंबई के लिए सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है।

लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने एडेन मार्करम का विकेट जल्दी गंवा दिया जो नौ रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विल जैक्स ने निकोलस पूरन को आउट कर लखनऊ को बड़ा झटका दिया जो 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ के कप्तान एक बार फिर विफल रहे और चार रन बनाकर पवेलियन लौटे। मिचेल मार्श ने हालांकि कुछ हद तक टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन बोल्ट ने उनकी पारी का अंत कर दिया। मार्श 24 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए।

लखनऊ ने डेविड मिलर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा और उन्होंने आयुष बडोनी के साथ साझेदारी निभाने की कोशिश की। बोल्ड ने बडोनी को 35 रन पर पवेलियन भेजा और फिर मिलर भी बुमराह का शिकार बने। मिलर 24 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में बुमराह ने अब्दुल समद और आवेश खान के भी विकेट चटकाए। रवि बिश्नोई ने दो छक्के लगाकर आंकड़ा कम करने का प्रयास किया, लेकिन कॉबिन बॉश ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। पारी की अंतिम गेंद पर बोल्ड ने दिग्वेश राठी को बोल्ड कर लखनऊ की पारी का अंत किया। मुंबई के लिए बुमराह के अलावा बोल्ट ने तीन विकेट लिए, जबकि विल जैक्स को दो और बॉश को एक विकेट मिला।

आरसीबी ने लिया दिल्ली से बदला, 7 विकेट से हराया

नई दिल्ली। आईपीएल 2025 के 46वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया है. आरसीबी की इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या. दोनों ने चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. विराट ने 51 और क्रुणाल ने 73 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 162 रन बनाए थे. जवाब में आरसीबी ने एक समय सिर्फ 26 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर विराट और क्रुणाल ने दमदार बल्लेबाजी से अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की. इस तरह RCB ने दिल्ली से बेंगलुरु की हार का बदला भी ले लिया.

अक्षय तृतीया पर घर बैठे खरीदें सोना, पाएं कैशबैक

नई दिल्ली। अक्षय तृतीया के पर्व के नजदीक आने के साथ ही डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे और पेटीएम डिजिटल गोल्ड पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं. इसके दो फायदे हैं- एक तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का रिवाज बना रहेगा और दूसरी तरफ नए जमाने में डिजिटलाइजेशन की सुविधा से लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा. इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है. फोन पे 24 कैरेट यानी कि 99.99 परसेंट शुद्ध डिजिटल गोल्ड में 2000 रुपये या उससे अधिक की एकमुश्त खरीद पर 1 परसेंट तक का कैशबैक (अधिकतम 2,000 रुपये तक) दे रहा है. यह ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल को एक बार की खरीदारी पर ही मान्य है. इसमें SIP-बेस्ड खरीदारी शामिल नहीं है. इसके अलावा, CaratLane स्टोर या वेबसाइट पर डिजिटल गोल्ड रिडीम करने वाले ग्राहकों को भी डिस्काउंट मिलेगा. इन्हें सोने के सिक्कों पर 2 परसेंट की छूट मिलेगी, जड़े हुए आभूषणों पर 5 परसेंट की छूट मिलेगी।

पहले किया महंगा फिर कर दिया सस्ता, सोने के पीछे ट्रंप का खेल

नई दिल्ली। सोने को यूं ही 'सोता हुआ दैत्य' नहीं कहा जाता. इतिहास गवाह है कि कई सालों तक सोना एक दायरे में ठहरा रहता है और फिर अचानक तेज़ी से दौड़ लगाता है. अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2022 तक सोने की कीमतें लगभग 1,700 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी रहीं. लेकिन नवंबर 2022 से हालात बदल गए. सोना एक दम से भागा और इस महीने 3,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया. ये अब तक का सबसे महंगा भाव है. हालांकि, बाद में इसमें थोड़ी गिरावट भी देखी गई. बड़ी बात ये है कि सोने के सस्ते और महंगे होने, दोनों के पीछें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैसले एक बड़ी वजह हैं.

पहले भी बढ़े थे सोने के दाम

वैसे, इससे पहले भी अक्टूबर 2018 से अगस्त 2020 के बीच ऐसा ही धमाका हुआ था, जब सोना 1,130 डॉलर प्रति औंस से चढ़कर 1,984 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था, यानी करीब 75 फीसदी की बढ़त सिर्फ दो साल में. इस बार की तेजी 2023 में शुरू हुई, जब सोने ने 13 फीसदी की छलांग लगाई और 2024 में भी कहानी दोहराई गई, इस बार 27 फीसदी की बढ़त के साथ.

ट्रंप की वजह से बढ़े सोने के दाम

अब आप सोच रहे हैं कि अचानक से सोने में इतनी तेजी कैसे आई, तो आपको बता दें, इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह रही है, ट्रंप के नए टैरिफ्स. 2025 में ट्रंप के टैरिफ ऐलान ने माहौल को और गरमा दिया. ट्रंप ने सभी देशों पर 'रेसिप्रोकल टैरिफ' लगाने का ऐलान किया, जिससे वैश्विक व्यापार पर भारी दबाव बनने का डर फैल गया. व्यापार युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं ने सोने को सपोर्ट दिया और इस साल अब तक सोना 25 फीसदी उछल चुका है. लेकिन हर रफ्तार को कहीं न कहीं ब्रेक भी लगता है. ऐसा ही सोने के साथ भी हुआ।

पहलगाम हमले के बाद आईपीएल में सुरक्षा करेगा "वज्र सुपर शॉट"

नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसका असर आईपीएल मैचों में भी देखा गया. आईपीएल के मैच जिन स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, वहां सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है. इस हथियार का नाम वज्र सुपर शॉट है, जो आसमान में बाज की तरह नजर रखता है. वज्र सुपर शॉट एक हल्का, हाथ में पकड़ा जाने वाला एंटी-ड्रोन हथियार है जो 4 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का पता लगाने और उनके संचार संकेतों को बाधित करने में सक्षम है, जिससे संभावित खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर किया जा सकता है. BBBS की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसकी पोर्टेबिलिटी और अनुकूली फ्रीक्वेंसी जैमिंग इसे भीड़ भरे स्टेडियम जैसे गतिशील वातावरण के लिए आदर्श बनाती है. शनिवार को ईडन गार्डन्स में हुए मैच में वज्र सुपर शॉट की तैनाती की गई थी. बीसीसीआई सुरक्षा के लिहाज से कोई लापरवाही नहीं करना चाहती.

अनंत अंबानी बने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर

1 मई से संभालेंगे नई जिम्मेदारी

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनंत अंबानी को कंपनी का पूर्ण-कालिक निदेशक नियुक्त किया है. रिलायंस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी ने कहा कि बोर्ड ने ह्यूमन रिर्सोसेज, नॉमिनेशन और रिमेन्युरेशन कमेटी की सिफारिश पर 1 मई, 2025 से पांच साल के लिए मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की नियुक्ति को अप्रूवल दे दिया है, जो अब शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है.

रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़े अनंत

अनंत फिलहाल कंपनी के नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. अब वह रिलायंस के कार्यकारी नेतृत्व का हिस्सा बनेंगे. अनंत रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड से जुड़े हुए हैं. इनमें मार्च 2020 से जियो प्लेटफॉर्म्स, मई 2022 से रिलायंस रिटेल वेंचर्स और जून 2021 से रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी शामिल हैं. सितंबर 2022 से वह रिलायंस फाउंडेशन के भी बोर्ड मेंबर हैं.

ईशा और आकाश संभाल रहे ये जिम्मेदारी

बोर्ड ने अगस्त 2023 में अनंत के साथ-साथ ईशा और आकाश अंबानी को कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी और शेयरधारकों ने अक्टूबर 2023 में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी. जहां आकाश अंबानी 2022 से रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन हैं, वहीं, ईशा अंबानी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड कामकाज संभाल रही हैं. अपने दोनों भाई-बहनों में से आकाश ही पहले हैं, जिन्हें रिलायंस इंडस्ट्री में कार्यकारी निदेशक की भूमिका मिली है. अनंत ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन की पढ़ाई की है.

अमेरिका और चीन के टैरिफ वार को अवसर बनाएगी योगी सरकार

2030 तक निर्यात को तीन गुना करने का लक्ष्य

प्रयागराज। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वार को उत्तर प्रदेश खुद के लिए अवसर बनाने की तैयारी कर रही है. वैसे तो दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच अपने-अपने वर्चस्व के लिए शुरू टैरिफ वार पूरे देश के लिए एक मौका है. राज्य की योगी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं (एक्सप्रेस वे, सामान्य एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय जलमार्ग) का विस्तार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश की संभावनाएं अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ जाती हैं. MSMEs भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, फिर भी क्यों हैं बीमा से दूर छोटे कारोबार, बड़ी चुनौती: बीमा के बिना MSMEs कितने सुरक्षित हैं? जब संकट आए, तो कौन बचाए? MSMEs के लिए बीमा का बढ़ता महत्व

इन्वेस्ट यूपी को और प्रभावी बनाएगी सरकार

सरकार इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का संभव प्रयास भी कर रही है. सरकार नई निर्यात नीति लाने जा रही है. इसमें इन्वेस्ट यूपी को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट की देश-दुनिया में ब्रांडिंग के लिए सरकार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो भी आयोजित करती है. इस साल भी 25 से 27 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा. इस बार आयोजन का पार्टनर देश वियतनाम होगा.

गृह मंत्रालय सख्त कहा; सभी पाकिस्तानियों को तय समय पर छोड़ना पड़ेगा भारत देश

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी हिदायत, दंडात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी

शहर सत्ता/रायपुर। उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वे केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे लेकिन रविवार को कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय के भीतर देश छोडऩा होगा, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम पाकिस्तानी पीडित लोगों की चिंता करते हैं कई लोग सब कुछ छोड़कर यहां आए हैं हम केंद्र से इस मामले में मार्गदर्शन लेंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसे 1897 पाक नागरिक रह रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टिप्पणी करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 1800 बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची मिली है, जिनकी पूरी जांच की जा रही है। इसके बाद इन अवैध घुसपैठियों को बंगाल पुलिस और बी एस एफ के हवाले कर दिया जाएगा। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से दो पाक नागरिक गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत में वीजा प्रवास पर आये सभी पाकिस्तानी नागरिकों को लौटने की मियाद पूरी हो गई है। ऐसे में अब भी कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और छुपकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में रह रहे हैं। आज रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेतांतर्गत दो पाक नागरिकों को पुलिस ने खोजकर निकल लिया और उन्हें कब्जे में लेकर निर्धारित समय सीमा में राज्य से बहार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पीसीसी चीफ बैज ने की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भत्सर्ना

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सरकार के मंत्री स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके चलते पहलगाम में आतंकी अटैक हुए जिसमें 28 लोग दिवंगत हुए, कई लोग घायल हैं। आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से संघ भाजपा उनके अनुषांगिक संगठनों ने आतंकी हमले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, असफल रहे। कश्मीर के पर्यटकों ने भाजपा के हिंदू-मुस्लिम फसाद करने वाले बयानों का खंडन किया। वहां गए पर्यटकों ने कहा कि वहां के मुसलमान अटैक के बाद लगातार उनके साथ में है, उनको मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, भाजपा का यह प्रयास असफल होने के बाद अब भाजपा के नेता और मंत्री जनता को ही इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल के बयान की कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल पहलगाम आतंकी हमले के लिए देश के 140 करोड़ जनता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पीयूष गोयल कह है कि देश के 140 करोड़ जनता देशभक्त नहीं है अगर देशभक्त होते तो आतंकी हमला नहीं होता इस प्रकार से बयान देकर पीयूष गोयल ने देश की जनता को सुरक्षा देने में असफल मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा कर रहे है। पीयूष गोयल का बयान गैर जिम्मेदाराना और आतंकी हमले में दिवंगत हुए लोगों का अपमान है, उनके परिजनों के जख्मों को कुरेदने वाला है।

भू-माफियाओं को संरक्षण देने नामांतरण प्रक्रिया में परिवर्तन

ग्रामसभा और तहसीलदार के अधिकारों को बाईपास करके ऑटोमैटिक नामांतरण से आम जनता चिंतित

शहर सत्ता/रायपुर। नामांतरण का अधिकार उप पंजीयकों को दिए जाने और ऑटोमेटिक नामांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह भू-माफियाओं के इशारे पर खेल रही है। सरकार के इस फैसले से आम जनता की जमीन पर खतरा बढ़ गया है।

नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित ग्रामसभा और तहसीलदार के अधिकारों को बाईपास करने से भू माफियाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा करके जमीन हथियाने का खेल आसान हो जाएगा। नए नियम में बिना दावा आपत्ति के, बिना इस्तेहार प्रकाशन के, बिना नोटिस तामिल किए ही अब नामांतरण हो जायेगा। सवाल यह है कि ऐसे नामांतरण के पश्चात ऋण पुस्तिका किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? राजस्व अभिलेख का संधारण कौन करेगा? गलत नामांतरण पर सुनवाई कौन करेगा? क्योंकि पंजीयक के न्यायिक अधिकार नहीं होते। साय सरकार का फोकस आम जनता का हित नहीं बल्कि भू माफियाओं के अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने में है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं जिसमें भू माफियाओं ने जमीन क्रेता को बताएं बिना ही बैंकों में कर्ज हेतु दर्ज जमीन या बंधक भूमि को बेच दिया और इस तरह की जमीन की रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय में हो भी जाती है लेकिन जब नामांतरण के लिए मामला तहसील और संबंधित ग्राम सभा तक पहुंचता है तो इस तरह की त्रुटियां/फर्जीवाड़े उजागर हो पाते है। अब जब नए आदेश के अनुसार उप पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतरित हो जाएगा तो ऐसे फर्जीवाड़े को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यदि नए आदेश के मुताबिक बिना किसी जांच के नामांतरण पूरा हो जाता है, तो असली मालिक को बिना सूचना के ही जमीन से हाथ धोना पड़ेगा।

भूपेश की संवेदना, हुए दुख में शामिल...

पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल समता कालोनी, रायपुर में पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुए कारोबारी स्व. दिनेश मिरानिया के निवास पर उनके शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

एम्स रायपुर में हुई पहली सफल किडनी पेयर (स्वैप) ट्रांसप्लांट

रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, नई एम्स संस्थाओं में पहली बार और छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी संस्थान में पहली बार सफलतापूर्वक स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney Paired Donation - KPD) किया है। यह उपलब्धि अंतिम चरण के गुर्दा रोग (ESRD) से जूझ रहे रोगियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्वैप ट्रांसप्लांट में, वह रोगी जिसे जीवित किडनी दाता तो उपलब्ध होता है लेकिन ब्लड ग्रुप या HLA एंटीबॉडी असंगतता के कारण प्रत्यारोपण संभव नहीं होता, वह दूसरी असंगत जोड़ी के साथ अंगों का आदान-प्रदान कर ट्रांसप्लांट करा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों असंगत जोड़े सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत बिलासपुर के दो ESRD रोगी (उम्र 39 और 41 वर्ष) जिनका तीन वर्षों से डायलिसिस चल रहा था, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। उनकी पत्नियां किडनी दान के लिए आगे आईं, लेकिन उनके रक्त समूह उनके पति से मेल नहीं खाते थे। पहली जोड़ी का ब्लड ग्रुप B+ और O+ था, जबकि दूसरी का O+ और B+। दोनों पत्नियाँ अपने पति को किडनी देना चाहती थीं, लेकिन ब्लड ग्रुप असंगति के कारण यह संभव नहीं था। इस चुनौती को दूर करने के लिए एम्स रायपुर की टीम ने स्वैप ट्रांसप्लांट की योजना बनाई जिसमें प्रत्येक महिला ने दूसरी जोड़ी के पति को किडनी दान दी, जिससे रक्त समूह की संगति सुनिश्चित हो सकी और प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया।

यह स्वैप ट्रांसप्लांट 15 मार्च 2025 को किया गया और दोनों दाता एवं प्राप्तकर्ता स्वस्थ रूप से ट्रांसप्लांट आईसीयू में चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

डॉ. विनय राठौर ने बताया कि लगभग 40 से 50 प्रतिशत जीवित किडनी दानदाता रक्त समूह या HLA एंटीबॉडी असंगति के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, "स्वैप ट्रांसप्लांट उन रोगियों के लिए जीवन रक्षक विकल्प है जिनके पास इच्छुक लेकिन असंगत दाता होते हैं। समय पर ट्रांसप्लांट, डायलिसिस की तुलना में बेहतर जीवन गुणवत्ता और दीर्घायु प्रदान करता है।" यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानी और विशेष योजना की मांग करती है, जिसमें SOTTO छत्तीसगढ़ से विशेष स्वीकृति आवश्यक होती है और यह केवल निकट संबंधियों के बीच ही अनुमत होता है। हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को NOTTO ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर स्वैप ट्रांसप्लांट की योजना को क्रियान्वित करने की सिफारिश की है ताकि जैविक असंगति वाले रोगियों को भी प्रत्यारोपण का लाभ मिल सके।

डॉ. अमित शर्मा, विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी ने बताया कि स्वैप ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि जहाँ एकल ट्रांसप्लांट करना अपेक्षाकृत सरल होता है, वहीं स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए महीनों की योजना, चार ऑपरेशन थिएटर, चार एनेस्थेटिस्ट और चार ट्रांसप्लांट सर्जनों की एक साथ व्यवस्था करनी होती है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को अब मिलेगी नई ऊंचाइयां

मंजूरी और तय समय सीमा में मिलेगी सेवाएं

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही, कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए 60 दिन, बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए 60 दिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृति के लिए 30 दिन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसी तरह नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति 300 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र 90 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। भवन निर्माण से संबंधित पांच चरणों जैसे भवन योजना स्वीकृति, परिवर्तन या पुनरीक्षण की अनुमति, ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण की अनुमति, प्लिंथ स्तर स्वीकृति तथा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना हेतु पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। स्टार्टअप इकाइयों के पंजीकरण के लिए भी 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा केंद्र और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी द्वारा प्रश्नों का प्रत्युत्तर 7 दिनों में तथा प्रश्नों और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सेवा क्षेत्र की इकाइयों के प्रश्नों का समाधान भी 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्शे पर और अधिक तेजी से अपना स्थान बनाने में सफल होगा।

गांधी भवन में स्थापित होगा सौर ऊर्जा सिस्टम

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और अहम कदम उठाते हुए रायपुर स्थित गांधी भवन में सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य भवन की विद्युत आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करना है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय और राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के बीच इस संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गांधी भवन में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और उसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों अध्यक्षों ने परियोजना को शीघ्र अमल में लाने के लिए परस्पर समन्वय स्थापित करने पर सहमति जताई। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ की हरित ऊर्जा नीति को मजबूती देगी, बल्कि गांधी भवन जैसे ऐतिहासिक स्थल को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग का प्रेरणादायक उदाहरण भी बनाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के प्रचार-प्रसार एवं उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है और यह परियोजना उसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

मन की बात

PM मोदी को पसंद आया दंतेवाड़ा का साइंस सेंटर

शहर सत्ता/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम की 121वीं एपिसोड में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का जिक्र किया। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि, आज भारत के युवा तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो इलाके कभी पिछड़ेपन और हिंसा के लिए पहचाने जाते थे। अब नवाचार के केंद्र बन रहे हैं। जहां कभी हिंसा और अशांति का साया था। आज वहां बच्चे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर भी कहा कि, देश के लोगों का खून खौल रहा है। पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र आज पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जहां बच्चों को थ्री-डी प्रिंटर, रोबोटिक कार जैसी मॉडर्न तकनीकों के बारे में बताया जाता है।

- **कहा- जहां कभी हिंसा का साया था, आज वहां बच्चे टेक्नोलॉजी-इनोवेशन के लिए आगे बढ़ रहे**

विज्ञान केन्द्र है वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केंद्र : साय

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि, दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केंद्र बन रहा है, जो विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार की दुनिया से जोड़ने का मोटिवेशनल माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री की यह सराहना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्साह वर्धक संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को 'मन की बात' के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं। देश भर में हो रहे सकारात्मक प्रयासों को साझा कर एक प्रेरक वातावरण तैयार करते हैं।

विवेकानंद में जुटे राष्ट्र निर्माण के लिए बुद्धिजीवी

शहर सत्ता/रायपुर। विवेकानंद नगर क्षेत्र में आज समाजिक सद्भाव टोली के तत्वावधान में एक भव्य सामाजिक सद्भाव सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य सर्व समाज को संगठित कर आपसी भेदभाव एवं भिन्नताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर होना था। आयोजन में विवेकानंद नगर, माना बस्ती, बनसी, माना केम्प, बोरियाकला, शद्धानी दरबार, दुमरतराई, ठेमरी, देवपुरी, अमलीडी, प्रियदर्शनी नगर, पचपड़ी नाका, काशीराम नगर, महावीर नगर, पुरैना, पेंशन बाड़ा, टैगोर नगर, शैलेन्द्र नगर, सिविल लाइन, कटोरा तालाब से लेकर श्याम नगर क्षेत्र तक के विभिन्न जातिगत समाजों के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील, जज एवं समाज सेवा से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए "व्यक्ति धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म" के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में अभूतपूर्व उत्साह और एकता का माहौल देखने को मिला। समाजसेवी चंद्रशेखर देवांगन जी ने अपने उद्बोधन में कहा, "भारत के प्रत्येक समाज में मूलभूत सद्भावना भरी हुई है, जिसे व्यवहार में लाकर हम भारत की वैश्विक पहचान को पुनः स्थापित कर सकते हैं।" रायपुर महानगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्री महेश बिल्ला जी ने कहा, "अब समय आ गया है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित न रहकर राष्ट्र जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएं। पंचतत्वों की चिंता करना आज समाज का दायित्व बन गया है।"

मंच संचालन भोजराज साहू द्वारा कुशलता से किया गया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस प्रकार के आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित किया जाए, जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी त्रिलोकचंद बड़ड़िया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समाज को निरंतर जागरूक और संगठित रहना आवश्यक है।"

सम्मेलन में अनिल स्वर्णकार, सिद्धार्थ प्रकाश श्रीवास्तव, गिरिश सिंह, श्री मंतूराम, प्रशांत सिन्हा, श्री रविकांत, विक्रम देवांगन, श्याम पांडे, मनीष चंदराकर, प्रमेश चंडोलकर, श्याम कार्तिक, रमेश पटेल, प्रकाश जोशी, शैलेश, भागीरथी पांडे, अद्वैत भाकरे, संजू साहू, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, सचिन मेघानि, अमर गिदवानी समेत अनेक समाजसेवियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई से मिली सफलता

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने यूपीएससी में चयनित अभिषेक अग्रवाल को दी शुभकामनाएं

रायपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 243वीं रैंक हासिल करने श्री अभिषेक अग्रवाल को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शुभकामनाएं दी और शॉल और श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले श्री अग्रवाल ने युवाओं से अपील की कि वे सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई की बदौलत सफलता हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी में मेहनत और लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसके सफलता के लिए उन्होंने अपने माता-पिता को श्रेय दिया। उल्लेखनीय है कि श्री अभिषेक अग्रवाल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्री उमेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं।

अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सिविल सर्विसेस परीक्षा में यह उनका छठवां अटैम्प्ट था। उन्होंने लगातार पांच बार मेंस की परीक्षा दी है तथा तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इस वर्ष उन्हें परीक्षा में रैंक 243 हासिल हुआ है। इसके पहले वर्ष 2021 में उनका चयन 254 रैंक के साथ आईआरएस के पद पर हो चुका है। वर्तमान में श्री अग्रवाल भारतीय वन सेना के अधिकारी हैं। उन्होंने डीपीएस स्कूल रायपुर और आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरा करते ही वर्ष 2016-17 में उनका चयन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए हुआ। श्री अभिषेक अग्रवाल कहते हैं कि मुझे व्यापक क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को करियर चुना। अभिषेक अग्रवाल युवाओं से कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग के साथ आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है।

चाल, चरित्र और चेहरे के साथ जुबान भी हैं बदशक्ल...

सुकांत राजपूत/रायपुर

शहर सत्ता। मामूली से जमीन दलाल से फिल्म प्रोडक्शन हॉउस का मालिक बनने का सफर तय करना ही किसी की सूरत, सीरत, खुश किस्मती के साथ उसकी कामयाबी बयान नहीं करती। कमाल तो तब होता है जब उसमें सहीं और गलत की शिनाख्त करने का माद्दा भी हो और बखत भी। छत्तीसगढ़ की परंपरा, परिधान, संस्कृति और संस्कार को संवारने वाले छालीवुड में ऐसों की दखल बढ़ जाये जो बदजुबान, बदशक्ल और बदमिजाजी के साथ बॉलीवुड की तर्ज पर छालीवुड में भी भाईगिरी करने पर आमादा हो तो समझो बिरादरी का बुरा वक्त हो गया है।

बदजुबानी सुधारने के बजाये कथित फिल्म निर्माता ने शहर सत्ता के कला समीक्षक को दी धमकी

मामला शहर सत्ता के सातवें अंक में प्रकाशित एक खबर का है। 'छालीवुड को ले डूबेगी, नफरत और बदजुबानी' को लेकर एक कुख्यात फिल्म निर्माता की आपत्तिजनक टिप्पणी पर शहर सत्ता के कला समीक्षक ने खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रमाणित थी फिर भी खामोश रहने के बदले फिल्म प्रोडक्शन हॉउस के उस कथित भाई ने हमारे ही अधिकृत रिपोर्टर को कॉल करके धमकी दे डाली। खैर, शहर सत्ता और हमारे रिपोर्टर ऐसी गीदड़ भभकी से खौफजदा कभी नहीं होंगे। लेकिन जमीन दलाली से कमाए काले पैसों से फिल्म निर्माता बने उस शख्स के द्वारा दफ़न किये उन सभी गड़े मुर्दे भी अब कफ़न फाड़कर हमसे उनका राज खोलेंगे और शहर सत्ता साप्ताहिक अख़बार का पाठकों से यह वादा भी है कि हम फिल्म इंडस्ट्रीज के ऐसे बदनुमा शख्स की खबर को अपनी सुर्खियां हमेशा बनाते भी रहेंगे।

पहले भी अभद्र हरकतों पर हुई है एफआईआर

मामला चंद महीनों पहले जिले के ग्राम बिटकुली में सतनाम धर्म के झंडे का अपमान का है। खुद की थकी-हारी और पिटी फिल्म में दर्शकों की टिप्पणी पर गाली-गलौच में उतरने वाले फिल्म निर्माता की एक फिल्म के कलाकार, निर्देशक पर एफआईआर तक हो चुकी है। सतनामी समाज के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता निर्देशक के ऊपर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मामला बलौदाबाजार थाना क्षेत्र का था। ऐसे कई मामले हैं जिनका खुलासा हम समय समय पर करते रहेंगे।

फ़िल्म समीक्षा

सुहाग

अनुज शर्मा की नई फिल्म में इमोशनलव और टकराव का जबरदस्त तड़का

अनुज शर्मा स्टारर "सुहाग" एक दिलचस्प ट्रायंगल लव स्टोरी है, जिसमें गांव, प्यार और करियर के बीच फंसे रिश्तों की गहराई को छूने की कोशिश की गई है। फिल्म में पूजा (सृष्टि देवांगन), एक एग्रीकल्चर स्कॉलर के रूप में अजय (अनुज शर्मा) के गांव आती है। अजय पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है, लेकिन पूजा उसे ठुकरा देती है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ करियर पर है।

टूटे दिल के साथ अजय वापस लौटता है, लेकिन किस्मत उसे एक नया मोड़ देती है। उसका एक इंटरव्यू वायरल होता है और उसे विधायक की बहन खुशी (अनिकृति चौहान) पसंद करने लगती है। दबाव में अजय की शादी खुशी से हो जाती है।

तभी पूजा दोबारा लौटती है और कहानी में इमोशनल ट्विस्ट आ जाता है। अब देखना ये है कि अजय अपने दिल की सुनेगा या रिश्तों की मर्यादा निभाएगा। फिल्म में अनुज शर्मा, अनिकृति और सृष्टि का अभिनय दमदार है। सूरज महानंद का बैकग्राउंड स्कोर कहानी को ऊंचाई देता है, जबकि गानों और संवादों की भी सराहना हो रही है। हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा कमजोर है और कुछ सीन दोहराव भरे लगते हैं, फिर भी फिल्म भावनाओं से भरी है और दर्शकों को जोड़ने में सफल रहती है।

कुल मिलाकर – "सुहाग" एक पारिवारिक, इमोशनल ड्रामा है जिसे एक बार देखा जा सकता है।

रेटिंग: 2.5/5

सिद्धार्थ का इशारा समझता है उनका सिनेमैटोग्राफी कैमरा

8 बार 'बेस्ट सिनेमैटोग्राफर अवार्ड' से सम्मानित

50 से ज्यादा फिल्मों के बाद 'मोर छइयां भुइयां 3' में डीओपी

शहर सत्ता/रायपुर। बचपन से फिल्मी दुनिया से गहरा नाता रखने वाले सिद्धार्थ सिंह आज छत्तीसगढ़ी और भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा का एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बंगाली, राजस्थानी, ओड़िया और मराठी जैसी विविध भाषाओं में 50 से अधिक फिल्मों में अपने सिनेमैटोग्राफी कौशल का लोहा मनवाने वाले सिद्धार्थ सिंह को अब तक 8 बार 'बेस्ट सिनेमैटोग्राफर अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है।

सिद्धार्थ के करियर की शुरुआत बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से हुई थी, लेकिन मेहनत, जुनून और लगन ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया, जहाँ आज उनका नाम गुणवत्ता की पहचान बन चुका है। 'मोर भुइया 2', 'ले शुरू होगे माया के कहानी', 'डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2', 'राजा छत्तीसगढ़िया', 'मार डारे माया मा', 'वैदेही' जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने अपनी सिनेमैटोग्राफी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

अब सिद्धार्थ सिंह अपनी अगली फिल्म "मोर छइयां भुइयां 3" के साथ फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। निर्देशक सतीश जैन के निर्देशन में बनी यह फिल्म आगामी 16 मई को प्रदर्शित होने जा रही है। सिद्धार्थ इस फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उनके अनुसार, "मोर छइयां भुइयां 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मेरी भावनाओं, मेहनत और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति मेरे प्रेम का परिणाम है।"

रायपुर के क्यूट टैटू विलेन लवनित फिल्मी सफर के लिए तैयार

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर निवासी लवनित सिन्हा ने अपने जुनून और मेहनत से छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। बचपन से डांस के शौकीन लवनित ने मुंबई के टेरेंस लुईस अकादमी से डांस की पढ़ाई की और एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा। पिता के अस्वस्थ होने पर रायपुर लौटे लवनित ने डांस क्लासेस शुरू कीं और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

पहले पिता और फिर दूसरा सुनहरा अवसर मां के लिए छोड़ दिया

लवनीत हैं CSEB के बेस्ट क्रिकेटर, डांसर और एक्टर

उनकी फिल्मी यात्रा शॉर्ट मूवीज़ और "सजनी तोर मुस्कान" जैसे हिट वीडियो सॉन्ग से शुरू हुई। दिसंबर 2023 में "जवानी जिंदाबाद" से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया और मुख्य विलेन की भूमिका निभाई। इसके बाद "दस्तावेज़", "लगे हे मोला तोर लगन", "नाचा", "भभूत" और "डार्लिंग प्यार झुकता नहीं" जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि "छैया भुइया 3" में काम न कर पाने का उन्हें अफसोस है,

लवनित बताते हैं कि उन्हें बचपन से नेगेटिव रोल्स बेहद पसंद रहे हैं, लेकिन वे सभी प्रकार के किरदार निभाना चाहते हैं। "दस्तावेज़" फिल्म में उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका निभाई थी। आज उन्हें सबसे कम उम्र के विलेन के रूप में भी पहचाना जाता है। युवाओं को संदेश देते हुए लवनित कहते हैं, "सही मेंटर, मेहनत और सही दिशा जरूरी है। भ्रम न पालें, इंडस्ट्री में मौके हैं। वर्कशॉप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें।"

धार्मिक आस्था का अनूठा केंद्र बना यह मंदिर, दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

मां मातंगी देती हैं भक्तों को 'कर्ज'

मुराद पूरी होने पर माता को भक्त लौटाते हैं दोगुनी रकम

पर्यटन संवाददाता/सुमित यादव
मोबाईल नंबर 7987832355

देश में तमाम मंदिर ऐसे हैं जहां श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं, पर छत्तीसगढ़ में एक मंदिर ऐसा भी है जहां माता रानी अपने भक्तों को 'कर्ज' देती हैं, और वो भी खुले मन से। यह मंदिर मां मातंगी दिव्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से कुछ दूर बीरेझर जीजामगांव में स्थित है। यह अनूठा मंदिर श्रद्धा, परंपरा और चमत्कार का केंद्र है, जहां भक्त खजांची के थैले से एक नोट निकालते हैं और उसे माता रानी से प्राप्त 'धार्मिक ऋण' मानकर अपने जीवन में लगाते हैं।

कैसे मिलती है 'माता रानी' से कर्ज की मान्यता?

मंदिर परिसर में माता रानी के समक्ष खजांची की एक मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के सामने एक विशेष थैला रखा गया है, जिसमें विभिन्न मूल्य के नोट होते हैं। मान्यता है कि भक्त उस थैले में आंखें बंद कर हाथ डालते हैं और जो पहला नोट उन्हें प्राप्त होता है, उसे अपने व्यापार या नौकरी में लगाते हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी मिसाल

यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष है, बल्कि इससे सामाजिक सहयोग की भावना भी मजबूत होती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है, और श्रद्धा के बल पर वे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

मान्यता और श्रद्धा का संगम

यह धन माता रानी की ओर से दिया गया कर्ज होता है, जो ईमानदारी और मेहनत से लगाया जाए तो कई गुना होकर लौटता है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और आर्थिक समृद्धि इस कर्ज की सौगात मानी जाती है। श्रद्धालु जब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, तो दो गुना या अधिक राशि अर्पित कर इस ऋण को चुकाते हैं।

देशभर से पहुंचते हैं श्रद्धालु

यह परंपरा अब इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां आकर माता रानी से 'कर्ज' हैं। हर उम्र और वर्ग के लोग जैसे व्यापारी, कर्मचारी, छात्र सभी यहां अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं।

गर्मियों में मैनपाट की वादियां दे रही हैं सुकून

अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी में जहां अधिकांश स्थानों पर तापमान चढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट अपनी ठंडी फिजाओं और हरियाली से लोगों को राहत दे रहा है। समुद्र तल से लगभग 3781 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्थल को "छत्तीसगढ़ का शिमला" कहा जाता है, और गर्मियों में यह पर्यटकों के लिए एक आदर्श ठिकाना बन गया है।

मैनपाट की वादियां, घने जंगल, बहते झरने और सुहानी ठंडी हवाएं यहां आने वालों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा अनुभव कराती हैं। टाइगर प्वाइंट, जलजली, मेहता प्वाइंट, तिब्बती मठ और उल्टा पानी जैसे स्थल रोमांच और रहस्य से भरे हैं। विशेष रूप से "जलजली" में धरती का हल्का-हल्का हिलना सैलानियों के लिए अनूठा आकर्षण है। ठंडे मौसम में पैराग्लाइडिंग का आनंद लेना, घाटियों का नजारा देखना और झरनों की कल-कल ध्वनि के बीच समय बिताना गर्मी से राहत पाने का बेहतरीन तरीका है। यहां की साफ हवा और शांति मानसिक सुकून भी देती है।

कैसे पहुंचे: मैनपाट अंबिकापुर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से निजी वाहन या टैक्सी के जरिये आसानी से पहुंचा जा सकता है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है।

विशेष आकर्षण

ठंडी जलवायु	:	गर्मी से राहत पाने के लिए परफेक्ट
प्राकृतिक रहस्य	:	जलजली, उल्टा पानी जैसे अद्भुत स्थल
एडवेंचर	:	पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग के अवसर
सांस्कृतिक अनुभव	:	तिब्बती मठ और बौद्ध संस्कृति
हरियाली और शांति	:	प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श

साप्ताहिक शहरसत्ता

उरांव राजवंशीय विष्णुदेव के सुशासन तिहार का बखान कर रहे लाभार्थी

राम राज्य में सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल रखा जाता था तो वह थे गरीब, वनवासी और समाज के अंतिम वर्ग का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन तिहार साय सरकार इस तबकों के द्वार-द्वार पहुंचकर उनकी हर जरूरतों की पूर्ति तत्काल कर रही है। पिछले पांच सालों तक तत्कालीन शासकों की बात जोहती छत्तीसगढ़ का यह तबका अब साय के सुशासन में अपनी साडी हसरतों को पूरा होते देख रहा है। यह हम नहीं विष्णुदेव साय सुशासन के लाभार्थी खुद बयान कर रहे हैं...मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ सरकार द्वार द्वार की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी अगर उदासीनता बरता तो वह उसके शासकीय कार्यकाल के लिए अभिशाप भी साबित होगा। अब तक कई अधिकारी, कर्मचारी जनता के हितों की अनदेखी किये हैं उनपर तत्काल कार्रवाई भी की गई है। देखिये उरांव राजवंशीय और संघर्ष चुनौतियों को पार करके छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव बने मुख्यमंत्री के सुशासन का बखान करते लाभार्थी...

हितग्राहियों का तत्काल बन रहा श्रमिक कार्ड

सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम भंवरमरा निवासी मथुरा बाई एवं श्रीमती रोमिन साहू द्वारा श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। श्रम विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों की जांच व परीक्षण किया गया और आवेदकों को श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा निवासी आशा विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत असंगठित कर्मकार दर्जी प्रवर्ग अंतर्गत पंजीकृत कर श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। आवेदिका आशा विश्वकर्मा को मंडल के नियमानुसार सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राम भोथीपार महराजपुर निवासी ठाकुर राम एवं चन्द्रकला राय द्वारा निर्माण श्रमिक कुली कार्य बताते हुए श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत निर्माणी श्रमिक के रूप पंजीकृत करते हुए श्रमिक कार्ड बनाया गया है।

आइस बॉक्स और मछली जाल से खुले रोजगार के नए द्वार

सिंघनपुर के टिकेश्वर सतनामी को मछली विक्रय के दौरान ताजगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती थी लेकिन विभाग द्वारा प्रदत्त आइसबॉक्स से अब वे मछलियों को लंबे समय तक संरक्षित रख पाएंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके व्यवसाय में स्थायित्व भी आएगा। टिकेश्वर बताते हैं, कि"पहले मछलियों को जल्दी बेचना पड़ता था, वरना खराब होने का डर रहता था। अब आइसबॉक्स की मदद से मैं मछलियों को दूर के बाजारों तक भी अच्छे हालत में बेच पाऊंगा। इससे मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से ग्राम गोड़पाली की निवासी श्रीमती गंगाबाई निषाद ने मछली पकड़ने के लिए जाल प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। उनके इस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग द्वारा उन्हें "मत्स्यपालन प्रसार योजना" के अंतर्गत मछली पकड़ने हेतु जाल उपलब्ध कराया गया। गंगाबाई निषाद लंबे समय से मछली पालन के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करती आ रही हैं। अब जाल प्राप्त होने से उन्हें अपनी आजीविका को और सुदृढ़ करने का अवसर मिला है।

ऋण पुस्तिका में सुधार होने से ऋषि कुमार के चेहरे पर आई मुस्कुराहट

धरसीवा विकासखंड के ग्राम बाना निवासी ऋषि कुमार का ऋण पुस्तिका में नाम सुधारने का आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पुस्तिका में त्रुटि सुधरवाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था लेकिन सुधार नहीं हो पाया। श्री ऋषि ने सुशासन तिहार के बारे में सुना और अपनी समस्या आवेदन के रूप में समाधान पेटी में डाली। उनकी शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों ने उन्हें फोन किया और सभी मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय बुलाया। तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे के मार्गदर्शन में ऋषि कुमार के दस्तावेजों के जांच के बाद उन्हें नई ऋण पुस्तिका जारी की गई। नई ऋण पुस्तिका पाकर उनका चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। सुशासन तिहार के जरिए शासन-प्रशासन न सिर्फ समस्याएं सुन रहा है, बल्कि त्वरित समाधान कर जनता के दिलों में भरोसा भी जगा रहा है।

दिव्यांग दीपक महिलांग अब किसी पर निर्भर नहीं

"अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने कार्य खुद कर सकता हूँ।" ये शब्द हैं बेमेतरा के मारो गाँव के निवासी दीपक महिलांग के, जो 90% दिव्यांगता के बावजूद आज आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हैं। यह बदलाव संभव हो सका है सुशासन तिहार 2025 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त बैटरी चालित ट्रायसायकल की मदद से। दीपक महिलांग एक ग्रामीण परिवेश से हैं, जहाँ परिवहन की सीमित सुविधाएँ दिव्यांगजनों के लिए बड़ी बाधा बनती थीं। लेकिन जैसे ही उन्हें ट्रायसायकल प्राप्त हुआ, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वे स्वतंत्र रूप से घर से बाहर आ-जा सकते हैं, छोटे-मोटे काम कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग ले पा रहे हैं। उन्होंने बताया, "पहले हर जगह जाने के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अब मैं खुद बाजार जा सकता हूँ, पंचायत बैठकों में शामिल हो सकता हूँ। दीपक समाज कल्याण की योजना के तहत आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनकी मासिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं।

पठारीडीह में 3 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग का ऐसे कटी राह

सुशासन तिहार के अंतर्गत आमजनों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सुशासन तिहार के पहले चरण में आमजनों की समस्या को जाना गया और दूसरे चरण में उनका निराकरण तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में धरसीवा ब्लॉक के ग्राम पठारीडीह के निवासियों ने सुशासन तिहार के माध्यम से इलाके में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की थी। उनके आवेदन पर एक्शन लेते हुए तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे ने टीम का गठन किया और संबंधित दस्तावेजों की जांच की। शिकायत सही पाए जाने पर राजस्व अमले द्वारा कुल 3 एकड़ जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए रास्ता काटने की कार्रवाई की गई। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हमारी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए।

बी-1 और खसरा मिला तो खिल गया संतराम साहू का चेहरा

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले के अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता के साथ आवेदनों पर कार्रवाई कर आमजन को राहत दिलाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पिपरहट्टा निवासी संतराम साहू ने सुशासन तिहार के अंतर्गत अपने जमीन के अभिलेख दुरूस्त कराने का आवेदन दिया था। आवेदन प्राप्त होते राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संतराम को कार्यालय बुलाया। जमीन संबंधी सारे दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तहसीलदार विनोद साहू के मार्गदर्शन में उनका बी-1 और खसरा नंबर की कॉपी सौंपी गई। दस्तावेज हाथ में आते ही संतराम साहू ने बताया कि लंबे समय उन्हें अपने जमीन के दस्तावेजों के लिए शासकीय कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ा। संतराम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आमजनों की सभी मांग और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो रही है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-22683361, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।